

## जनजातियों का संरक्षण

### प्रीलिमिंस के लिये:

जनजाति, अमेज़न वर्षावन, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 243 ।

### मेन्स के लिये:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अमेज़न वर्षावन](#) में एक स्थानिक जनजाति के अंतिम ज्ञात सदस्य की दशकों तक अकेले रहने के बाद मृत्यु हो गई है ।

- ब्राज़ील में एक असंबद्ध स्थानिक जनजाति के अज्ञात व्यक्ति को 'मैन ऑफ द होल' के रूप में जाना जाता था क्योंकि उसे अक्सर जमीन में खोदे गए गड्ढों में आश्रय लेते हुए देखा जाता था ।
- उनकी मृत्यु के परिणामस्वरूप अब कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर से चर्चा है कि स्थानिक लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है ।

## भारत में जनजातियों की स्थिति:

- भारत में, अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत "अनुसूचित जनजाति" के रूप में पहचाना जाता है ।
- आजादी के बाद से देश में आदवासी आबादी का हिसा लगातार जनगणना के हिसाब से बढ़ता रहा है ।
- वर्तमान समय में भारत की जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या के लगभग 9% के करीब पहुँच रही है ।

## जनजातीय समुदाय की सामान्य चिंताएँ:

- घटती जनसंख्या:
  - स्थानिक समुदाय घटती आबादी का सामना कर रहे हैं ।
- गरीबी:
  - इन स्थानिक समुदायों में से अधिकांश अत्यधिक गरीबी में रहते हैं । वे कुपोषण से पीड़ित हैं और बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं है ।
- वन क्षेत्रों का क्षरण:
  - वन क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास से वन क्षेत्रों का ह्रास हुआ है जो आदवासी समुदाय के अस्तित्व का प्रमुख आधार है ।
- अधिकारों को पहचानने में विफलता :
  - वन संसाधनों पर स्थानिक समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने में असमर्थता भी एक चिंता का विषय है ।

## स्थानिक समुदायों का महत्त्व:

- जैव विविधता का संरक्षण:
  - जबकि स्थानिक लोग विश्व के सतह क्षेत्र के एक चौथाई हिस्से के स्वामी हैं, कब्जा करते हैं या उपयोग करते हैं वे विश्व की शेष जैव विविधता के 80% की रक्षा करते हैं ।
  - जलवायु और आपदा जोखिमों को अनुकूलित करने, कम करने और कम करने के बारे में उनके पास महत्त्वपूर्ण ज्ञान और विशेषज्ञता है ।
  - भारत के जातीय लोगों ने जैव विविधता के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आदवासियों के पवित्र उपवनों में वनस्पतियों

और जीवों का संरक्षण किया है।

■ **भाषाओं का संरक्षण:**

○ वशिव की अधिकांश सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 370-500 मिलियन स्थानिक लोगों के साथ, वे वशिव में लगभग 7000 भाषाओं का प्रयोग करते हैं।

■ **शून्य भूख लक्ष्य में योगदान:**

- स्थानिक लोगों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें अत्यधिक अनुकूलनीय होती हैं।
- वे **सूखे, ऊँचाई, बाढ़ और तापमान के किसी भी प्रकार के चरम से बच सकते हैं**। नतीजतन, ये फसलें लचीली कृषि स्थापित करने में मदद करती हैं।
- इसके अलावा क्विनोआ, मोरगिा और ओका कुछ ऐसी स्थानिक फसलें हैं जो हमारे खाद्य आधार का वसितार और विविधता लाने की क्षमता रखती हैं। ये शून्य भुखमरी हासिल करने के लक्ष्य में योगदान देंगे।

## भारत में जनजातीय समूहों की समस्याएँ:

- **प्राकृतिक संसाधनों पर नयितरण का नुकसान** : जैसे-जैसे भारत का औद्योगिकरण हुआ और आदवासी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई, आदवासी अधिकारों को कम किया गया, और राज्य के नयितरण ने प्राकृतिक संसाधनों पर आदवासी नयितरण को बदल दिया।
  - **संरक्षित वनों** और राष्ट्रीय वनों की अवधारणा को प्रचलन में आने के साथ, आदवासियों ने खुद को अपने सांस्कृतिक परिक्षेत्र से उखड़ा हुआ महसूस किया और आजीविका के कोई सुरक्षित साधन नहीं थे।
- **शिक्षा की कमी**: जनजातीय क्षेत्रों में, अधिकांश स्कूलों में बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिसमें न्यूनतम शिक्षण सामग्री और यहाँ तक कि न्यूनतम स्वच्छता प्रावधान भी शामिल हैं।
  - शिक्षा से तत्काल आर्थिक लाभ न होने के कारण आदवासी माता-पिता अपने बच्चों को लाभकारी रोजगार में लगाना पसंद करते हैं।
  - अधिकांश जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम **आधिकारिक/क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किये गए हैं**, जो आदवासी छात्रों से दूर हैं।
- **वसिस्थापन और पुनर्वास**: बड़े इस्पात संयंत्रों, बजिली परियोजनाओं और बड़े बाँधों जैसे प्रमुख क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया के लिये सरकार द्वारा जनजातीय भूमिके अधिग्रहण से जनजातीय आबादी का बड़े पैमाने पर वसिस्थापन हुआ।
  - **छोटानागपुर क्षेत्र**, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदवासी इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
  - इन आदवासियों का शहरी क्षेत्रों में **प्रवास** उनके लिये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनता है क्योंकि वे शहरी जीवन शैली और मूल्यों को अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएँ**: आर्थिक पिछड़ेपन और असुरक्षित आजीविका के कारण, आदवासियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे किमलेरिया, हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारी का प्रसार।
  - कुपोषण से जुड़ी समस्याएँ जैसे आयरन की कमी और **एनीमिया, उच्च शिशु मृत्यु दर आदि** भी प्रबल होती हैं।
- **लैंगिक मुद्दे**: प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास, विशेष रूप से वनों के वनिाश और तेजी से सकिडते संसाधन आधार के कारण, महिलाओं की स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है।
  - खनन, उद्योग और व्यावसायिकरण के लिये जनजातीय क्षेत्रों के खुलने से आदवासी पुरुषों और महिलाओं को बाजार अर्थव्यवस्था के जटिल संचालन के लिये उजागर किया गया है, जिससे उपभोक्तावाद और **महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ावा मिला है**।
- **पहचान का क्षरण**: तेजी से, आदवासियों की पारंपरिक संस्थाएँ और कानून आधुनिक संस्थानों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं, जो आदवासियों में अपनी पहचान को बनाए रखने के बारे में आशंका पैदा करते हैं।
  - **जनजातीय बोलियों** और भाषाओं का वल्लिप्त होना चिंता का एक और कारण है क्योंकि यह आदवासी पहचान के क्षरण का संकेत देता है।

## अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान कए गए बुनियादी सुरक्षा उपाय:

- भारत का संविधान 'जनजाति' शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, हालाँकि, **अनुसूचित जनजाति** शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 (i) के माध्यम से जोड़ा गया था।
  - यह निर्धारित करता है कि 'राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों या भागों के कुछ हिसिंसाँ या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
  - संविधान की पाँचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक **जनजाति सलाहकार परिषद** की स्थापना का प्रावधान करती है।
- **शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय:**
  - **अनुच्छेद 15(4)**: अन्य पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
  - **अनुच्छेद 29**: अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल हैं)
  - **अनुच्छेद 46**: राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। शोषण।
  - **अनुच्छेद 350**: विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृत के संरक्षण का अधिकार,
- **राजनीतिक सुरक्षा उपाय:**
  - **अनुच्छेद 330** : लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 332**: राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण
  - **अनुच्छेद 243**: पंचायतों में सीटों का आरक्षण
- **प्रशासनिक सुरक्षा:**
  - **अनुच्छेद 275**: यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा

राज्य सरकार को विशेष नधिप्रदान करने का प्रावधान करता है।

## अनुसूचति जनजातियों के लिये हाल की सरकार की पहल:

- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

## आगे की राह:

- उन्हें प्रथम श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार करने का समय:
  - शिक्षा या प्रौद्योगिकी जैसे विकास का लाभ उन तक पहुँचना चाहिये लेकिन साथ ही उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक में नहीं बदलना चाहिये।
  - वे प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी के नागरिक बने रहना चाहिये ताकि उनके आत्मविश्वास, उनके सशक्तिकरण और उनकी स्वायत्तता और उनके स्वाभिमन की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये और यह शताब्दी सहति सभी आदवासी समुदायों पर लागू होता है।
- पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करना:
  - केंद्र और राज्यों दोनों की सरकारों को जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार को नीति की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के रूप में मान्यता देनी चाहिये और राष्ट्रीय जनजातीय योजना सहति पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करना चाहिये।
- वरिष्ठ और संस्कृति का संरक्षण:
  - पर्याप्त न केवल गुणवत्तापूर्ण पोषण और स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करके आदवासियों की आबादी की रक्षा के लिये निर्देशित किए जाने चाहिये, बल्कि उनकी वरिष्ठ, संस्कृति, भाषा, कला, परंपराओं और संवेदनाओं को संरक्षित करने के प्रयासों की भी आवश्यकता है।
- आर्थिक उत्थान:
  - आदवासियों के आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के उपाय करके आदवासियों की स्थिति को कम करने के लिये कदम उठाने की जरूरत है।
  - आदवासियों के विकास के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम समुदाय के अद्वितीय चरित्र के अनुरूप होना चाहिये और आवश्यकता आधारित होना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

भारत के संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नजि पार्टियों को आदवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित कया जा सकता है? (2019)

- (A) तीसरी अनुसूची
- (B) पाँचवी अनुसूची
- (C) नौवी अनुसूची
- (D) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- अनुसूचति क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पाँचवी और छठी अनुसूची के साथ अनुच्छेद 244 में नहिति प्रावधानों और पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनुसूचति क्षेत्रों में खनजि रयियतों का अनुदान नरिदेशित है। 1996 और अनुसूचति जनजात और अन्य पारंपरिक वन नवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या आदवासियों के हतियों की रक्षा करने वाले कोई अन्य प्रासंगिक वैधानिक अधिनियम।
- पाँचवी अनुसूची के तहत, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा नरिदेश दे सकते हैं कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम राज्य में अनुसूचति क्षेत्र या उसके कसि हिस्से पर लागू होगा या नहीं।
- इस प्रकार, पाँचवी अनुसूची के तहत, खनन के लिये नजि पार्टियों को आदवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित कया जा सकता है। अतः विकल्प (B) सही है।

????

प्र. आप उन आँकड़ों की व्याख्या कैसे करते हैं जो दिखाते हैं कि भारत में जनजातियों में लगानुपात अनुसूचित जातियों के लगानुपात की तुलना में महिलाओं के लिये अधिक अनुकूल है? (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/protecting-the-tribes>

